IJNRD.ORG ISSN : 2456-4184
INTERNATIONAL JOURNAL OF NOVEL RESEARCH AND DEVELOPMENT (IJNRD) | IJNRD.ORG
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

ग्रामीण सामाजिक–आर्थिक विकास में मनरेगा की भूमिका: राजस्थान के संदर्भ में

Ram Swaroop Meena

(Research Scholar)

Faculty of Arts, Craft & Social Science

Tantia University, Sri Ganganagar

Under the Supervision of

Dr. Vishal Chhabra

(Professor)

Faculty of Arts, Craft & Social Science

Tantia University, Sri Ganganagar

प्रस्तावना

भारत एक कृषि प्रधान देश है। जहाँ जनसंख्या का एक बहुत बडा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के सीमित साधन, गरीबी, और बेरोजगारी जैसी समस्याएं आम है। इन समस्याओं के कारण संसाधनों की कमी के कारण विकास की गति धीमी रही है। विशेष रूप से राजस्थान जैसे राज्य, जहाँ जलवायु की कठोरता, जल सकंट और भूमि की अपर्याप्त उर्वरता ग्रामीण जीवन को चुनौतिपूर्ण बनाते हैं, वहाँ ग्रामीण विकास योजनाएँ अत्याधिक महत्त्वपूर्ण है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) 2005 में ऐसे ही समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। यह योजना न केवल रोजगार प्रदान करती है, बल्कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे को सुधारने में भी सहायक है। राजस्थान जो भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से जूझता है, इस योजना ने ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना और ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकसीत करना है। राजस्थान जैसे राज्य जहाँ भूमि का बड़ा हिस्सा मरुस्थलीय है, मनरेगा के माध्यम से रोजगार, और

संसाधन उपलब्ध कराना अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) 2005 में ऐसे ही समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। यह योजना न केवल रोजगार प्रदान करती है, बल्कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे को सुधारने में भी सहायक है। राजस्थान जो भौगोलिक और सामाजिक–आर्थिक चुनौतियों से जूझता है। राजस्थान में इस योजना ने ग्रामीण विकास के क्षेत्रो में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मनरेगा – एक परिचय

मनरेगा 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ । इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगारी को समाप्त करना और आजीविका सुरक्षा प्रदान करना है। प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिनों का रोजगार, प्रदान करना और ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकसित करना है।

विशेषताए

- ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करना जैसे–सड़क, जल निकास. और सिचाई सुविधा ।
- स्थानीय स्तर पर काम उपलब्ध कराना
- महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना
- न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करना ।

केन्द्र सरकार द्वारा वित्तिय वर्ष 2024–2025 के लिए नई मजदूरी दरे 1 अप्रैल 2024 से लागू कर दी गई हैं।

मनरेगा योजना के तहत सभी राज्यों में औसत दैनिक मजदूरी पहले के मुकाबले बढ़ा दी गई है। अब मनरेगा मजदूरी रेट 261 रूपए से बढ़ाकर 289 रूपए कर दिया गया है।

मनरेगा के उद्देश्य

1. प्राकृतिक संसाधनो का संरक्षण और बुनियादी ढांचे का विकास।

2 गरीबी उन्मूलन और आजिविका में सुधार ।

3. ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों का का गारंटीशुदा रोजगार प्रदान करना ।

4. यदि सरकार, रोजगार देने में असफल रहती हैं तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी।

5. इस अधिनियम में उन लोगों को वरीयता दी जाएगी जिनसे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी ।

6. महिलाओं का सशक्तिकरण ।

7. गांवों से शहरों की ओर होने वाले पलायन पर रोक लगाना।

साहित्य समीक्षा

संबंधित शोध साहित्य समीक्षा किसी शोध का अध्ययन का एक आवश्यक पक्ष होता है। इसमें शोधकर्त्ता शोध से संबंधित साहित्य का अवलोकन कर सूक्ष्म विश्लेषण के आधार स्वंय द्वारा किये जा रहे शोध के लिए नए आयाम व दृष्टिकोण का निर्धारण करता है। अतः साहित्य का पुनर्निरीक्षण किये जा रहे शोध को दिशा निर्देश व मार्ग निर्देशन में सहायता प्रदान कर शोध को गति प्रदान करता है। साहित्य का पुनरावलोकन कर शोधकर्ता न केवल पूर्व में किये गये शोधकार्यों के दोहराव को रोकता है। बल्कि नई प्राक्कल्पनाओं अभिप्रायपूर्ण तथा कल्याणकारी खोज भी करता है। साहित्य का पुनरावलोकन इस बात में भी मदद करता है कि शोध किस प्रकार, प्रयोजपूर्ण बन सकता है? और साथ ही शोध की अधिक यथार्थ व व्यवहारिक बनाने हेतू किन–किन तकनीकों व शोध सरंचनाओ का प्रयोग शोधार्थी द्वारा किया जाना चाहिए। साहित्य की समीक्षा करते समय विषय से जुड़े अध्ययनों की यथासम्भव शामिल करने का प्रयास किया है, जो इस प्रकार है।

1. इकबाल नारायण ने अपनी पुस्तक '' पंचायती राज एडमिनीस्ट्रेशन इन राजस्थान '' (1993) इस पुस्तक में नारायण जी ने पंचायती राज व्यवस्था का विस्तृत विश्लेषण किया है। इसमें पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना पर प्रकाश डाला है।

ग्रामीण विकास के प्रशासनिक तंत्र, जिलाधीश, खण्ड विकास अधिकारी, प्रसार अधिकारी तथा ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं के कर्तव्य व कार्यों का का उल्लेख किया है।

2. आर–एन, रैना की पुस्तक ''Impliment of National Rural Employment Guarantee.'' किताब महल प्रकाशन में मनरेगा योजना के क्रियान्वयन पर जोर दिया है। इन्होने इस अधिनियम के क्रियान्वयन दौरान होने वाली विभिन्न परिस्थितियों का वर्णन करते हुए सुझाव देने का प्रयास किया है।

महेश शर्मा ने अपनी पुस्तक ''महात्मा गांधी नरेगा'' (2014) प्रभात प्रकाशन में मनरेगा को ग्रामीण लोगों को रोजगार देने का सबसे बढ़िया जरिया बताया है। उन्होने मनरेगा की समीक्षा में बताया कि यह अधिनियम न केवल मांग पर आधारित काम का अधिकार देता है बल्कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिलाओं की अनिवार्य उपस्थिति से उनका ग्रामीण समाज को आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त किया ।

3. चन्द्रशेखर सी. और जे. घोष Public Works and Wages in Rural India

इस अध्ययन में बताया गया है कि मनरेगा के लागू होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तविक मजदूरी विशेषकर महिलाओं की मजदूरी बढ़ी। महात्मा गांधी नरेगा का ग्रामीण मजदूरों में महिला श्रमिको पर साकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

4. कुमार शशि बी और रेंगा सामी International Multidisciplinary Research germal में भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में ग्रामीण श्रमिको की भागीदारी के बारे में अध्ययन किया है।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र में यह जानने का प्रयास किया गया है कि महात्मा गांधी मनरेगा गरीबी, बेरोजगारी, संवेदनशील और गरीब लोगों की आय और, आजीविका सुरक्षा का एक स्थायी स्त्रोत उपलब्ध कराने रोजगार व ग्रामीण विकास की समस्या का समाधान करने में किस हद तक सफल रही है। अध्ययन का उद्देश्य इस प्रकार हैः

1 मनरेगा का सामाजिक सशक्तिकरण पर प्रभाव का अध्ययन ।

2. बुनियादी ढांचे और सामुदायिक विकास पर प्रभाव का अध्ययन ।

3. ग्रामीण पंचायती राज सस्थाओं की भूमिका का अध्ययन ।

4. ग्रामीण रोजगार के अवसर पर प्रभाव का अध्ययन ।

मनरेगा का प्रभाव

सामाजिक आर्थिक परिपेक्ष्य में राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। जिसकी 70 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर करती है। राजस्थान में भूमि की गुणवत्ता में कमी, सूखा और सीमित सिंचाई सुविधाओं के कारण कृषि क्षेत्र में रोजगार की कमी है।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारी की संख्या अधिक है।

महिला श्रमिकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति कमजोर है।

इस प्रकार राजस्थान में मनरेगा की सफलता इसकी स्थानीय चुनौतियो की मध्य नजर रखते हुए कार्यान्वयन में है।

- वर्ष 2023 तक राजस्थान में लगभग 1.5 करोड़ परिवारों को मनरेगा का लाभ मिला।
- 10,000 से अधिक जल के साधन विकसित किए गए है।
- जल संरक्षण, जलाशय और तालाबो का निमार्ण हुआ।
- ग्रामीण सड़कों का सुधार हुआ और निमार्ण हुआ जिससे बाजार तक पहुंच में सुधार हुआ।

सामाजिक और आर्थिक प्रभाव

महिला सशक्तिकरण

मनरेगा ने ग्रामीण महिलाओं को काम के अवसर प्रदान कर उनकी आय में वृद्धि की। इसका प्रभाव उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और निणर्य लेने की क्षमता पर भी पड़ा है।

ग्रामीण जीवन में सुधार

मनरेगा योजन के कारण सामुदायिक ससांधनो जैसे सड़क, पानी और बिजली की उपलब्धता ने जीवन स्तर को बेहतर बनाया है। मनरेगा में ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योग दिया है। इससे श्रमिकों की नियमित आय सुनिश्चित हुई जिससे उनके खर्च करने की क्षमता में वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में

रोजगार के अवसर मिलने से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन कम हुआ है। इस प्रकार मनरेगा योजना का ग्रामीण विकास पर साकारत्मक प्रभाव देखने को मिला।

चुनौतियों और समस्याएँ

मनरेगा ने ग्रामीण विकास में इसके महत्वपूर्ण योगदान दिया है फिर भी इसके कार्यान्वयन में कई समस्याएं बनी हुई है। प्रशासनिक बाधाएं श्रमिको को समय पर भुगतान नहीं मिलना। श्रमिकों की शिकायतों का समाधान न होना । राज्य और केन्द्र सरकार के बीच धन राशि आवंटन में असमानता, फर्जी श्रमिकों के नाम पर धन का दुरुपयोग होना ,काम के गुणवत्ता मानकों का पालन न होना । जागरुकता की कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की योजना की प्रक्रिया और उनके अधिकारों के बारे में जानकारी की कमी।

समाधान और सुझाव

मनरेगा के प्रभाव को बढ़ाने और इसकी चुनौतियों को दूर करने के लिए अनेक कदम उठाए जा सकते है जैसे

- नीति सुधार से प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाना ।
- स्थानीय भागीदारी से ग्राम पंचायतो और स्थानीय समुदाय को योजना के कार्यान्वयन में अधिक जिम्मेदारी देना।

भ्रष्टाचार रोकने के लिए तकनीक का उपयोग कार्यों की निगरानी के लिए जियो–टैगिंग और ऑनलाइन ट्रेकिंग सिस्टम लागू करना है ऑनलाइन उपस्थिति और आधार कार्ड के माध्यम से मजदूरी का सीधा बैंक खातों में समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करना। योजना निमार्ण और कार्यों में स्थानीय समुदाय और पंचायतो की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्ति व जागरूक करना।

निष्कर्ष

मनरेगा राजस्थान के ग्रामीण सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण योजना साबित हुई है। इसने रोजगार प्रदान करने के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास, महिला सशक्तिकरण और सामुदायिक उत्थान को बढावा दिया है। हालांकि, योजना को अभी भी भ्रष्टाचार, प्रशासनिक

अनियितताओं और जागरूकता की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन उचित सुधारों से यह योजना और अधिक प्रभावशाली हो सकती है। राजस्थान जैसे राज्य में जहाँ जलवायु और सामाजिक संरचना की कठोरताएँ विकास को धीमा करती है वहाँ मनरेगा ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार और सामुदायिक विकास का एक मजबूत आधार प्रस्तुत किया है।

सदर्भ ग्रंथ सूची

1. जलान, विमल, भारत का भविष्य, राजनीति, अर्थशास्त्र और शासन, पेगुइन बुक्स इडिया प्रा.लि, गुड़गाव, हरियाणा, 2007।

2. सेन, अमर्त्य और द्रेज, ज्यां (2019) भारत और उसके विरोधाभास, राजकमल प्रकासन प्रा.लि. नई दिल्ली, पेज न० 205–207

3. सेन, अमर्त्य, गरीबी और आकाल, राजपाल प्रकाशन एण्ड संन्स,नई दिल्ली 2011

4 द्रेज, ज्यां (2019), झोलावाला अर्थशास्त्र, वाणी प्रकाशन, भारत में सामाजिक विकास की रीति नीति, नई दिल्ली, 2020

5. जालान विमल, भारत की अर्थनीति, 21वीं सदी ओर, राजकमल प्रकाशन प्रा०लि० नई दिल्ली 2003

6. दत्ता, पूजा और अन्य (2014) कार्य करने का अधिकार बिहार में भारत की रोजगार गारंटी स्कीम का मूल्यांकन करते हुए।

7. रंगरातन, सी., भारत की अर्थनीति, नये आयाम राजपाल प्रकाशन एण्ड संन्स, नई दिल्ली 2010

8. भास्कर, अंजोर और पंकज यादव (2015) 'अंत भला तो सब भला झारखण्ड में महात्मा गांधी नरेगा कुंओं का आर्थिक मूल्यांकन', मानव विकास संस्थान पूर्वी केन्द, रांची झारखण्ड, 2015 द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को प्रस्तुत रिपोर्ट।

9. दत्त पी., आर. मुर्रगई, एम. रैवेलियन और डी. वल्ले (2012) 'क्या भारत की रोजगार गारंटी स्कीम रोजगार गारंटी देती है?' इकॉनोमिक एण्ड पॉलिटिकल

10 सिन्हा, बी. (2013) महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत सृजित परिसम्पत्तियों की संभरणीयता को बढ़ाने की गंजाइश की पहचान करना। भोपाल भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ।

11. लयू, वाई. और सी. बेरट (2012) भारत की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गार टी स्कीम में असंगत गरीब समर्थक लक्ष्य निर्धारण, दिल्लीः आईएफपीआरआई।

12. मनरेगा समिक्षा–2, 2012–14,

ग्रामिण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

नरेगा वेबसाइट पर दर्ज आंकड़े।

राजस्थान सरकार के मनरेगा से सबधित आँकड़े ।

योजना आयोग की रिर्पोट।

विभिन्न शोध पत्र और लेख ।

International Research Journal
IJNRD
Research Through Innovation